

दक्षिण एशिया में राज्य-राष्ट्र अंतर्द्वंदः नेपाल राज्य का अध्ययन

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय
लखनऊ से राजनीति विज्ञान विषय में
पी-एच०डी० की उपाधि
हेतु प्रस्तुत

शोध सारांश



शोध निर्देशक
प्रो० रिपु सूदन सिंह
राजनीति विज्ञान विभाग

शोधार्थी
विकास शुक्ला
नामांकन संख्या: 1414/16

राजनीति विज्ञान विभाग
अम्बेडकर अध्ययन विद्यापीठ
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
लखनऊ-226025

2022

शोध सारांश

1.1 भूमिका—

समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय पहचान के मुद्दे पर दो दृष्टिकोण अपना प्रभुत्व रखते हैं प्रथम राष्ट्र—राज्य का विचार और द्वितीय राज्य—राष्ट्र की अवधारणा। हम सभी जानते हैं राष्ट्र—राज्य का विचार वेस्टफेलिया की संधि (1648) का उत्पाद है फिर भी राज्य—राष्ट्र (State-Nation) राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में एक नवीन घटना है। राज्य—राष्ट्र (State-Nation) उपनिवेशवाद के अंत (Decolonization) का उत्पाद है। तृतीय विश्व के नवीन निर्मित स्वतंत्र राज्य अभी तक राष्ट्र—निर्माण की प्रक्रिया में व्यस्त है। प्रस्तावित अध्ययन के दो भाग हैं। प्रथम—सामान्य रूप में दक्षिण एशिया में राज्य—राष्ट्र (State-Nation) अंतर्द्वंद (Dilemma) और द्वितीय—विशेष रूप में नेपाल राज्य में राज्य—राष्ट्र अंतर्द्वंद।

प्रस्तावित अध्ययन को तीन दृष्टिकोणों के माध्यम से समझा जा सकता है। प्रथम—ऐतिहासिक दृष्टिकोण जो सांस्कृतिक परम्परा का वर्णन करता है। द्वितीय—आर्थिक दृष्टिकोण जो नेपाल के भू-बध्य (Land Locked) होने के नाते उसके विकास में उत्पन्न हो रहे अवरोधों और नेपाल राज्य की राजनीतिक स्थिति के कारण चीन और भारत के मध्य में प्रतियोगिता का वर्णन करता है और तृतीय—राजनैतिक दृष्टिकोण जो नेपाल की स्थिति का वर्णन यथार्थवादी एवं नव-यथार्थवादी सिद्धांत के प्रकाश में परिभाषित करने का प्रयास करता है। भू-बध्य होने के नाते अपनी वैश्विक अवस्थिति के चलते नेपाल के समक्ष अस्तित्व की चुनौतियाँ हैं। जो मार्क्सवाद—लेनिनवाद और माओवाद से उत्पन्न नेपाल के संदर्भ में वैचारिकी भी एक चुनौती है। उपरोक्त विभिन्न सैद्धांतिक अवधारणाओं के संदर्भ में उक्त विषय को प्रस्तुत करने का प्रयास है जो निम्नलिखित है—

(a) राज्य-राष्ट्र (state-nation) की अवधारणा

राज्य-राष्ट्र की अवधारणा को 1996 में Linz और Stepan ने प्रस्तुत किया। दोनों लेखकों ने राज्य-राष्ट्र (state-nation) और राष्ट्र-राज्य (nation-state) को तुलनात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से विश्लेषित किया है—

1. राष्ट्र-राज्य में जागरूकता और लगाव एक मुख्य सांस्कृतिक परम्परा (Cultural Civilizational Tradition) की तरफ होता है जबकि राज्य-राष्ट्र (State-Nation) में जागरूकता और लगाव एक से अधिक मुख्य सांस्कृतिक सभ्यता परम्पराओं (Multi-Cultural Civilizational Tradition) की तरफ होता है।
2. राष्ट्र-राज्य मुख्य रूप से एक सांस्कृतिक पहचान, एक आधिकारिक भाषा और एकात्मकता की इकाई (Unity of Oneness) की समरूपता (homogenization) से सम्बद्ध होता है जबकि राज्य-राष्ट्र (State-Nation) एक से अधिक सांस्कृतिक पहचानों, भाषाओं, सामान्य राजकीय प्रतीकों को मान्यता प्रदान करता है। राज्य-राष्ट्र विभिन्नता की एकता (Unity of Diversity) के साथ सम्बद्ध होता है।
3. राष्ट्र-राज्य मुख्यता एकीकृत राज्यों (Intigrated State) पर बल देता है वहीं दूसरी ओर राज्य-राष्ट्र (State-Nation) संघीय व्यवस्था पर बल देता है।
4. राष्ट्र-राज्य इकहरी पहचान (Single Identity) पर बल देता है जबकि राज्य-राष्ट्र (State-Nation) विविध पहचानों (Diversity Of Identity) पर बल देता है।

संक्षेप में — “राज्य राष्ट्र (State-Nation) प्रतीकों के माध्यम से जैसे-संविधान, समावेशी लोकतान्त्रिक संस्थाएं, मौलिक स्वतन्त्रता की गारंटी के साथ सकारात्मक नागरिक पहचान का निर्माण करता है।”

(b) राज्य और राष्ट्र में भेद

वर्तमान वैश्विक भू-भाग 195 राज्यों में विभाजित है जिनमें 192 संयुक्त-राष्ट्र के सदस्य हैं। इन राज्यों की सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हैं। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राज्यों को अपनी निर्धारित सीमाओं के अंदर अपनी सत्ता (authority) को क्रियान्वयन करने का अधिकार प्राप्त होता है। राज्य और राष्ट्र आधुनिक लोकतंत्र के आवश्यक तत्व हैं। जहां तक राज्य और राष्ट्र में भेद का प्रश्न है वह इस प्रकार है—

1. राज्य और राष्ट्र दोनों के तत्व भिन्न भिन्न होते हैं राज्य के चार तत्व होते हैं—जनसंख्या, भू-भाग, सरकार, संप्रभुता वहीं राष्ट्र लोगों का एक समूह होता है जो सामान्य संस्कृति, भाषा, इतिहास, पहचान को परस्पर साझा करते हैं।
2. राज्य एक राजनैतिक संगठन है वहीं राष्ट्र एक सामाजिक-सांस्कृतिक इकाई है।
3. राज्य के लिए संप्रभुता अनिवार्य तत्व है परन्तु राष्ट्र के लिए यह आवश्यक नहीं है।
4. राष्ट्र (nation), राज्य की तुलना में अधिक व्यापक धारणा है।

(c) दक्षिण-एशिया में राज्य-राष्ट्र अंतर्द्वंद

दक्षिण एशियाई राज्य बहुलवादी (pluralistic) प्रकृति के हैं क्योंकि ये राज्य विविध नृजातीय, सांस्कृतिक, भाषाई, पहचानों में विभाजित हैं। तुलनात्मक रूप से दक्षिण एशियाई राज्यों ने विविध प्रकार के आदिवासी, बहुसंख्य जातीय और नृजातीय समूह समाज में उर्ध्वाधर (vertical) और क्षैतिज (horizontal) आकार में विभाजित हैं। दक्षिण एशियाई राज्यों के पास समृद्ध सांस्कृतिक परम्परा है। दक्षिण एशिया 7 स्वतंत्र राज्यों का क्षेत्र है जहां विश्व की 1/6 प्रतिशत आबादी निवास करती है। भू-राजनीतिक दृष्टि से यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दक्षिण एशियाई राज्यों का समाज बहु-सांस्कृतिक, बहु-भाषाई, बहु-धार्मिक, बहु-मजहबीय, बहु-नृजातीय विशिष्टताओं को समेटें हुए है। दक्षिण एशिया में दो

परम्पराएँ मुख्य रूप से परिलक्षित होती हैं। प्रथम धार्मिक परंपरा है जिसका इतिहास 5000 वर्षों का है और दूसरी परंपरा पश्चिम एशिया में उत्पन्न अब्राहम की परंपरा है जिससे तीन रिलीजन—मजहब यथा यहूदी रिलीजन, क्रिश्चियन रिलीजन और इस्लाम मजहब की परंपरा रही है। जहां तक दक्षिण एशिया में राज्य—राष्ट्र (state-nation) अंतर्द्वंद (dilemma) का प्रश्न है तो सभी दक्षिण एशियाई राज्य “राज्य—राष्ट्र अंतर्द्वंद” (state-nation dilemma) का सामना कर रहे हैं क्योंकि एक राष्ट्र के रूप में ये सभी देश समान भाषा, संस्कृति, पहचान, धर्म मजहब इतिहास को परस्पर साझा करते हैं परन्तु एक राज्य के रूप में ये सभी अंतर्द्वंद से गुजर रहे हैं। दक्षिण एशियाई राज्यों में राज्य—राष्ट्र अंतर्द्वंद (state-nation dilemma) के मुख्य कारणों में —“सरकार का अस्थायित्व, लम्बे समय तक सैनिक शासन (पाकिस्तान और बांग्लादेश), नृजातीय संघर्ष, मजहबी संघर्ष पहचान और भागीदारी का संकट शामिल है” यह सभी अंतर्द्वंद दक्षिण एशिया में राज्य—राष्ट्र को स्थापित करने में बाधक रहे हैं।

(d) नेपाल में राज्य—राष्ट्र अंतर्द्वंद

नेपाल दक्षिण एशिया में एकमात्र जीवित राजतन्त्र के रूप में विद्यमान रहा है। लेकिन लंबी राजनीतिक उथल—पुथल वैचारिक आधार पर उत्पन्न हिंसक संघर्षों, विचार विमर्शों के उपरांत 20 सितम्बर 2015 को नेपाल में नया संविधान लागू हो गया और नेपाल को “संघीय प्रजातांत्रिक गणतन्त्र” घोषित कर दिया गया। परन्तु जहां तक नेपाल में राज्य—राष्ट्र अंतर्द्वंद (state-nation dilemma) का प्रश्न है तो अन्य दक्षिण एशियाई राज्यों की भांति नेपाल राज्य भी राज्य—राष्ट्र अंतर्द्वंद का सामना कर रहा है। नेपाल में राज्य—राष्ट्र अंतर्द्वंद को निम्नलिखित आधारों के माध्यम से समझा जा सकता है—

• माओवादी विद्रोह और राज्य—राष्ट्र अंतर्द्वंद

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल —माओवादी (CPN-M) ने नेपाली राज्य के विरुद्ध लंबे समय तक (1996—2006) सैनिक विद्रोह किया परन्तु नेपाल में राज्य—राष्ट्र

अंतर्द्धद CPN-M के द्वारा दशकों तक जारी सैनिक विद्रोह के कारण नहीं बल्कि नेपाल राज्य द्वारा अपने शासन पर प्रभुत्व और नियंत्रण न कर पाने के कारण यह अंतर्द्धद उत्पन्न हुआ। नेपाल में इस वैधानिक संकट के उत्पन्न होने के दो कारण रहें—

- i. 20वीं शताब्दी में निरंतर चलने वाले राजनीतिक आन्दोलन नेपाल राज्य में लोकतंत्र और संविधानवाद को स्थापित करने में विफल रहे।
- ii. नेपाली राज्य अपने नागरिकों को सरकारी/जनसुविधाएँ और सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहा।

इन कारणों से नेपाली राज्य कमजोर होता गया और गैर-राज्यकर्ता (non-state actors) माओवादी समूह के प्रभाव के कारण देश की सम्प्रभुता कमजोर होती गयी। इसके अतिरिक्त माओवादी, नेपाल राज्य में विदेशी अनुदान और गैरसरकारी संगठनों के संचालन के विरोधी हैं क्योंकि इनका तर्क है कि यह स्थिति नेपाल पर प्रभुत्व स्थापित करने की है।

• मधेशी आन्दोलन और राज्य-राष्ट्र अंतर्द्धद

20 सितम्बर 2015 को नेपाल में नया संविधान लागू होते ही नेपाल एक पंथनिरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित हो गया। परन्तु नेपाल राज्य के कुछ विशेष समूह मुख्यतः मधेशी समुदाय के लोग जो नेपाल के तराई क्षेत्र में निवास करते हैं और जिनकी आबादी नेपाली जनसंख्या की लगभग 50 प्रतिशत है नए संविधान से संतुष्ट नहीं है क्योंकि इनका मानना है कि नए संविधान में उनका बहिर्वेशन (exclusion) और भेदभाव हुआ है। अपनी मांगों को लेकर मधेशी समुदाय आन्दोलनरत है इनकी प्रमुख मांगें हैं—

1. अंतरिम संविधान के अनुच्छेद 63(3) को नए संविधान में पुनः लागू किया जाये।

2. नए संविधान के अनुच्छेद 283 को संशोधित किया जाये क्योंकि यह मधेशी समुदाय के लोगों को नेपाल राज्य का मूल निवासी नहीं मानता।

मधेशी समुदाय का यह आन्दोलन नेपाल को राज्य-राष्ट्र (state-nation) के रूप में विकसित होने की दिशा में एक प्रमुख चुनौती बनकर उभरा है।

• नृजातीय संघर्ष (ethnic conflict) और राज्य-राष्ट्र अंतर्द्वंद

नेपाल राज्य में नृजातीय समूहों की अत्यधिक विविधता है। नेपाल राज्य में नृजातीय समूह अपनी पहचान, भागीदारी के संकट को लेकर संघर्षरत है। नृजातीय समूहों का यह संघर्ष नेपाल को राज्य राष्ट्र के रूप में स्थापित होने के मार्ग में बाधक सिद्ध हो रहा है।

• आर्थिक अंतर्द्वंद और राज्य-राष्ट्र

नेपाल राज्य ऐतिहासिक रूप से आर्थिक गतिविधियों हेतु भारत पर निर्भर रहा है। ब्रिटिश समाज – वैज्ञानिक Piers Blaike का मानना है कि नेपाल में पूंजीवाद का विकास और भारत के साथ सम्बंध नेपाली राज्य की प्रकृति और सहयोग के बिना नामुमकिन है इनका विचार है कि भारतीय आर्थिक प्रक्रियाओं के विस्तार ने नेपाल राज्य की पर्वतीय आबादी की आर्थिक प्रक्रियाओं, संस्थाओं को कमजोर और विकलांग बना दिया है। नेपाल राज्य में भारतीय आर्थिक गतिविधियों ने एक प्रकार के अंतर्द्वंद (dilemma) को उत्पन्न करने का कार्य किया है।

1.2 शोध समस्या

विविधता सभी दक्षिण एशियाई राज्यों की वास्तविकता है। सभी दक्षिण एशियाई राज्य बहु-भाषाई, बहु-नृजातीय, बहु-मजहबी, बहु-धार्मिक, बहु-पहचान की विशेषताएँ लिए हुए हैं। दक्षिण एशिया के प्रत्येक राज्य में नृजातीय, भाषाई समूहों की विविधता पाई जाती है। ये सभी समूह भिन्न सामाजिक-राजनीतिक लामबंदी के स्तर पर हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने प्रत्येक आधार पर विश्व को एकीकृत करने में

महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है लेकिन "विविधता" पहचान के माध्यम से अस्तित्व में आती है, परन्तु पहचान (identity) अपनी विशिष्टता को सुरक्षित रखने हेतु वैश्वीकरण के लिए चुनौती उत्पन्न कर रही है। नेपाल इस दृश्य परि-घटना (Phenomenon) में अपवाद नहीं है ।

इस सन्दर्भ में नेपाल का उपलब्ध साहित्य नेपाल राज्य के समावेशी लोकतंत्र या वास्तविक लोकतंत्र की प्रकृति को चुनौती देता है । नेपाल एक मध्यम राज्य है जिसके समाज में संरचनात्मक विषमताएं विद्यमान हैं ।

1.3 साहित्य समीक्षा

Benedict Anderson ने अपनी (1979) में प्रकाशित पुस्तक, **Imagined Communities: Reflection on the Origine and Spread of Nationalism.** में राष्ट्र-राज्य की उत्पत्ति का विश्लेषण प्रस्तुत किया है। विभिन्न लेखकों ने राष्ट्र-राज्य और राज्य-राष्ट्र की उत्पत्ति पर विमर्श किया है। Anderson ने इस विमर्श को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्र-राज्य की उत्पत्ति को रेखांकित किया है। इनका मानना है कि राष्ट्र-राज्य का आरम्भ प्रिन्ट मीडिया के द्वारा हुआ है जैसे-समाचार पत्र और नयी तकनीक 1500 और 1600 A.D. में विकसित हुई, जिससे लोग नये तरीकों के माध्यम से अपने विचारों, संस्कृति, मूल्य, भाषा को परस्पर साझा करने लगे यहीं से राष्ट्र-राज्य की उत्पत्ति हुई। Anderson राष्ट्र-राज्य को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि "राष्ट्र लोगों का एक समूह है जो परस्पर सामान्य भाषा, संस्कृति, इतिहास को साझा करते हैं, जबकि राज्य एक राजनीतिक संगठन है जिसकी एक निर्धारित भू-भाग पर संप्रभुता होती है।"

T-K-Oommen ने अपनी (2002) में प्रकाशित पुस्तक **State Versus Nation in South Asia: Linking Language and Governence** में दक्षिण एशिया में राज्य बनाम राष्ट्र के विमर्श पर बल दिया है। इनका मानना है कि दक्षिण एशियाई राज्य बहु-सांस्कृतिक, बहु-भाषाई, बहु-नृजातीय, बहु-धार्मिक विशिष्टताओं से परिपूर्ण है। दक्षिण एशिया में

“राज्य और राष्ट्र” का विमर्श राष्ट्रीय एकीकरण योजना के तीन आयामों के आधार पर विचार करता है—

- (i) संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से राष्ट्रीय पहचान को परिभाषित करना।
- (ii) राज्य के समुदायों के मध्य सम्बंध सम्पूर्णतः लिए हुए होने चाहिए।
- (iii) इतिहास शिक्षा के द्वारा राजनीतिक समाजीकरण।

Oommen तर्क देते हुए कहते हैं कि सांस्कृतिक समरूपता (culturally Homogeneous) और राज्य-राष्ट्र की पश्चिमी यूरोपीय अवधारणा दक्षिण एशियाई राज्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। Oommen इसका कारण यह बताते हैं कि दक्षिण एशियाई राज्य सांस्कृतिक, भाषाई विविधता से परिपूर्ण हैं। अतः इस विविधता को समरूपता (Homogenize) प्रदान करना एक लोकतंत्र विरोधी प्रक्रिया होगी। Oommen ने अपने अध्ययन में यह स्पष्ट किया है कि दक्षिण एशियाई राज्यों में राष्ट्रीय पहचान को धार्मिक और अंतर-धार्मिक (religious and inter-religious) संघर्ष से बाहर निकालकर स्थापित करने का प्रयास चल रहा है।

Ishtiaq Ahmed ने अपनी पुस्तक (1996), **State, Nation and Ethnicity in South Asia**. में दक्षिण एशियाई राज्यों में राज्य राष्ट्र के अंतर्द्वंद को नृजातीयता, साम्प्रदायिकता और अलगाववाद के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास किया है। वह बल देते हुए कहते हैं कि सम्पूर्ण दक्षिण एशियाई राज्य अत्यधिक चुनौतीपूर्ण नृजातीय समस्या का सामना कर रहे हैं मुख्यतः श्री-लंका, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान इसका सामना कर रहे हैं।

इनका मानना है कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया नृजातीय और अलगाववादी समस्या को सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण सिद्ध कर रही है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में 1980 के दौरान से नृजातीय और साम्प्रदायिक समस्या और अधिक सशक्त हुई है। Ahmed नृजातीयता को व्यापक सन्दर्भ में परिभाषित करते हुए कहते हैं “नृजातीयता मनुष्य की ऐसी प्रवृत्ति है जो एक दूसरे के साझा धर्मों, भाषा, संस्कृति, प्रतीकों, एक दूसरे से जुड़ाव की भावना, विमर्श की साझा संरचना के साथ जुड़ी होती है।”

अपने अध्ययन में Ahmed ने बहुसांस्कृतिक उत्तर-औपनिवेशिक राज्यों को नृजातीय संघर्ष और अलगाववाद के सिद्धांतों के द्वारा वर्णित किया है इस सन्दर्भ में वह कहते हैं कि दक्षिण एशिया के राज्यों का आधुनिक राज्यों के साथ कमजोर जुड़ाव है, जहां एक ओर आधुनिक राज्य आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के चलते विकसित और मजबूत आर्थिक स्थिति में है वहीं दूसरी तरफ दक्षिण एशिया के राज्य नृजातीय संघर्ष, साम्प्रदायिकता और अलगाववादी स्थिति के कारण कमजोर स्थिति में है। इस सन्दर्भ में वह "राष्ट्र-राज्य योजना बनाम अलगाववादी योजना" को रेखांकित कर रहे हैं। वह कहते हैं कि राज्य और समाज के मध्य सकारात्मक तालमेल समाज की सांस्कृतिक और राजनीतिक विविधता को स्थापित करने में सहायक होगा।

Richard Burghar ने अपनी पुस्तक (1984), **The Formation of the Concept of Nation & State in Nepal-** में Burghar नेपाल राज्य में राज्य-राष्ट्र और राष्ट्र-राज्य के विमर्श को संकल्पना (concept) और राज्य के विचार (Idea of state) के सन्दर्भ में विश्लेषित किया है। Burghar राष्ट्र-राज्य का अर्थ बताते हुए कहते हैं कि "राष्ट्र-राज्य सरकार का एक रूप है, जिसमें सांस्कृतिक, भाषाई, विविध पहचान वाले समूह एक निर्धारित भू-भाग में रहते हैं।" Burghar का यह मानना है कि नेपाल में राज्य-राष्ट्र (State-Nation) का विचार वर्तमानकालीन सन्दर्भ में परिलक्षित नहीं होता है, क्योंकि दक्षिण एशियाई पार्श्वभाग (Southern Flank) में नेपाल राज्य के विस्तार के कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

इनके अनुसार नेपाली राज्य एक नयी समस्या का सामना कर रहा है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश इंडिया द्वारा सीमा के निर्धारण में विभिन्नता होने से उत्पन्न हुई है। वह मानते हैं कि नेपाल में राज्य-राष्ट्र की अवधारणा पश्चिमी है, जो उसके मूल समस्याओं और आंतरिक अंतर्द्वंद (Internal Dilemma) को सुलझाने में विफल रही है।

Nancy-E-Levine ने अपने लेख (1987), **Cast, State and Ethnic Boundries in Nepal.** में नृजातीय अंतर्द्वंद का विध्वेषण किया है इनके मत में नेपाल राज्य में एक तरफ

असीमित नृजातीय विविधता है वहीं दूसरी ओर अपेक्षाकृत नृजातीय समूहों का सीमित विरोध परिलक्षित होता है, जैसे कि—हिन्दू बनाम बुद्ध, आदिवासी बनाम जातीय, पर्वतीय बनाम मध्य पर्वतीय, मध्य पर्वतीय बनाम तराई। इनका तर्क है कि नेपाल राज्य में नृजातीय समूहों का यह अंतर्द्वंद्व नेपाल को राज्य—राष्ट्र के रूप में विकसित होने में एक बाधक के रूप में कार्य कर रहा है। नेपाल में वर्तमान नृजातीय समूहों के मध्य सम्बंध क्षेत्रीय नृजातीय व्यवस्था के मध्य ऐतिहासिक प्रक्रिया के सामंजस्य और राज्य की केन्द्रीयकरण की नीतियों का परिणाम है।

Levine का मानना है कि नेपाल राज्य के ह्युमला (Humala) और उत्तर पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में नृजातीय सामंजस्य की प्रक्रिया को समझने के लिए यह नृजातीय समूह एक शिक्षापृष्ठ स्थिति प्रदान करते हैं। ह्युमला (Humala) और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां नेपाल राज्य के प्रमुख नृजातीय समूह लंबे अंतराल से निवास के रहे हैं। Levine का तर्क है यह वह क्षेत्र भी है जहां गैर— हिन्दू नृजातीय समूह हिन्दू शासन के आधीन रहें हैं सम्पूर्ण नेपाल राज्य में ह्युमला (Humala) जनसंख्या का अपने नागरिकों के बीच भेदभाव नृजातीय पहचान (Ethnic identity) और जातीय प्रतिष्ठा (caste position) के आधार पर किया जाता है नेपाल राज्य इन अंतर्द्वंद्वों को सुलझाने में विफल रहा है। यह अंतर्द्वंद्व नेपाल में राज्य—राष्ट्र की प्रक्रिया में बाधक सिद्ध हो रहा है।

Jeevan Raj Sharma ने अपनी पुस्तक (2010), **On State Reconstruction in Nepal**¹ में नेपाल राज्य के पुनर्निर्माण की समस्याओं को रेखांकित किया है। अपने अध्ययन में वह उल्लेख करते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल—माओवादी (CPN-M) ने नेपाली राज्य के विरुद्ध लंबे समय तक सैनिक विद्रोह किया परन्तु 2006 में CPN-M और नेपाली राज्य के मध्य शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने के उपरांत माओवादियों का यह विद्रोह थम गया। वर्तमान कालीन नेपाल राज्य पुनर्निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहा है। 20 सितम्बर 2015 को नया संविधान लागू होते ही नेपाल संघीय

प्रजातंत्रात्मक गणतन्त्र के रूप में स्थापित हो गया। नेपाल राज्य पुनर्निर्माण की दिशा में जिन तात्कालिक समस्याओं का सामना कर रहा है उनमें प्रमुख हैं –

- निरंतर हिंसा, तराई क्षेत्र में राज्य के नियन्त्रण और उत्तर दायित्व का अभाव
- संघर्ष के पीड़ितों को न्याय और मुआवजे का प्रावधान करने में विफलता
- नृजातीय समूहों का संघर्ष
- ऐतिहासिक रूप से कमजोर, अधिकारविहीन समूहों की पहचान और उनके समावेशन का संकट
- मधेशी आन्दोलन

नेपाल राज्य में "राज्य पुनर्निर्माण (state reconstruction) का विमर्श विभिन्न मुद्दों को शामिल करता है –

- नृजातीय और क्षेत्रीय संघवाद
- सकारात्मक कार्यवाही (Affirmative action)
- समावेशी राज्य (inclusive state)
- जनवादी लोक तन्त्र
- पहचान समूहों की समस्याओं को रेखांकित करना

तात्कालिक विमर्श की यह प्रवृत्ति है की यह आंतरिक और बाह्य समस्याओं को राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सन्दर्भ में समझने का प्रयास करता है। नेपाली राज्य के विफल होने में भी यही कारक उत्तरदायी रहे हैं, जो निम्नलिखित हैं—

- नेपाली राज्य द्वारा सामाजिक सम्बंधों और राजनीतिक सत्ता के लोकतंत्रीकरण करने में विफलता

- विकास अनुदान होने के बावजूद नागरिकों को आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने में विफलता

नेपाल राज्य में राज्य पुनर्निर्माण के मार्ग में ये आधारभूत समस्याएँ हैं। अतः नेपाल में राज्य और राज्य पुनर्निर्माण में हिमालयी क्षेत्र के एकीकरण का भू-राजनीतिक विश्लेषण किये जाने की आवश्यकता है तथा वैश्वीकरण और भारतीय विस्तार को राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के व्यापक सन्दर्भ में देखा जाना चाहिए।

Alfred Stepan, Juan J. Linz and Yogendra Yadav ने अपनी (edt) पुस्तक (2011), **Crafting State&Nation: India and other Multi-national Democracies.** में सर्वप्रथम राज्य-राष्ट्र की अवधारणा को प्रस्तुत करते हुए कहा कि "राज्य- राष्ट्र "We Feeling" के साथ जुड़ी संकल्पना है, जिसमें लोग किसी विशेष समुदाय, संस्कृति, भाषा से जुड़ाव महसूस करते हैं।" इनका मानना है कि राज्य और राष्ट्र दोनों धारणाएं आधुनिक लोकतंत्र के लिए आवश्यक हैं। Linz और Stepan का यह मत है कि यदि कोई राज्य "राज्य-राष्ट्र" के आदर्श प्रकार के करीब है तो इसके नागरिकों के पास उपर्युक्त चार विशेषताएँ होनी चाहिए—

- राज्य के साथ सकारात्मक पहचान
- विविध परन्तु पूरक राजनीतिक पहचान
- राज्य की संस्थाओं पर अटूट विश्वास
- लोकतंत्र के लिए उच्चस्तरीय सकारात्मक समर्थन

राष्ट्र राज्य सिद्धांतकारों का केन्द्रीय दावा यह है कि केवल राष्ट्र-राज्य (Nation-State) ही राज्य के साथ पहचान और विश्वास को सुधार सकता है, जो लोकतान्त्रिक कार्यों के लिए आवश्यक है। परन्तु Linz और Stepan का मानना है कि राष्ट्र-राज्य (Nation-State) में "विविधता" शांतिपूर्ण और लोकतान्त्रिक तरीके से आकर नहीं ले सकती है क्योंकि यह स्थिति सिर्फ राज्य-राष्ट्र (State-Nation) में ही सम्भव है। राज्य-राष्ट्र (State-Nation), राज्य के प्रतीकों के द्वारा जैसे संविधान, समावेशी

लोकतान्त्रिक संस्थाएं, मौलिक स्वतन्त्रता की गारंटी के साथ सकारात्मक नागरिक पहचान का निर्माण करता है। Linz और Stepan अपनी इस पुस्तक में इस बात का उल्लेख करते हैं कि राज्य-राष्ट्र की नीतियाँ ऐसे राजनीतिक संस्थात्मक दृष्टिकोण के साथ जुड़ी होती हैं, जो एक से अधिक सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई पहचान का सम्मान करती हैं।

बी. सी. उप्रेती ने अपने लेख 'नेशनलिज्म इन साउथ एशिया ट्रेंड्स एंड इंटरप्रिटेशन' इंडियन जर्नल आफ पॉलीटिकल साइंस, Vol. XVII, No. 3 July & September, 2006. PP-535-544 में एशिया में राष्ट्रवाद का विश्लेषण प्रस्तुत किया है। इनके अनुसार दक्षिण एशियाई राष्ट्रवाद की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं जैसे कि पंथनिरपेक्ष राष्ट्रवाद, भाषा-सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, धार्मिक राष्ट्रवाद, आक्रमक राष्ट्रवाद इस प्रकार धर्म भाषा जातीयता आदि दक्षिण एशिया में राष्ट्रवाद के तत्व रहे हैं।

भारत में राष्ट्रवाद एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में उदार लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्षता का प्रतिनिधित्व करता है जिससे एकता की धारणा को बढ़ावा मिलता है। भारतीय राष्ट्रवाद को आकार प्रदान करने का कार्य भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने किया और इसके स्रोत ऐतिहासिक परंपराएं, राष्ट्रवादी आंदोलन, संविधान, लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्थाएं, पंथनिरपेक्षता, स्वतंत्रता और समानता तथा आधुनिकीकरण और विकास रहे हैं। हालांकि भाषाई, जातीय और क्षेत्रीयता की उभरती संकुचित प्रवृत्तियों ने अनेक विकृतियां उत्पन्न की हैं।

हुमा बाकी अपने लेख "डेमोक्रेटिक डेफिसिट इन साउथ एशिया" में कहती हैं कि दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में समान राजनीतिक प्रणाली नहीं है परंतु स्वतंत्रता के पश्चात अधिकांश दक्षिण एशियाई राज्यों ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया। सभी दक्षिण एशियाई देशों का लोकतांत्रिक करण की प्रक्रिया के साथ अनुभव मिलाजुला रहा है इस संदर्भ में आम धारणा यह है कि भारत में लोकतंत्र सफल रहा है और पाकिस्तान में विफल दक्षिण एशिया में भारत और श्रीलंका औपनिवेशिक शासन के शिकार रहे हैं। जिस कारण इन्होंने आर्थिक और सामाजिक विकास की गंभीर

समस्याओं का सामना किया है। उसके बावजूद भी यह दोनों देश लोकतांत्रिक बने हुए हैं। फिर भी दोनों राजनीतिक प्रणालियों को बार-बार उप राष्ट्रीय आंदोलनों नृजातीय संघर्षों और समाज के सभी वर्गों के हिंसक विरोध का सामना करना पड़ रहा है जो राज्य राष्ट्र अंतर्द्वंद को उत्पन्न करने में महती भूमिका का निर्वाह कर रहा है।

एस. डी. मुनि ने "द न्यू डेमोक्रेटिक वेब एंड रीजनल कोऑपरेशन इन साउथ एशिया, 2009" में दक्षिण एशिया में लोकतंत्र के विकास पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। एस. डी. मुनि कहते हैं कि दक्षिण एशिया के देशों में लोकतांत्रिक पुनरुत्थान हुआ है। सभी दक्षिण एशियाई देशों में अब तक लोकतांत्रिक व्यवस्था है सभी दक्षिण एशियाई देशों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुना है लेकिन लोकतंत्र के लिए यह संक्रमण अभी भी नाजुक और कमजोर है क्योंकि दक्षिण एशिया में लोकतांत्रिक विफलतायें भी आयी हैं जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश में सैनिक तख्तापलट, आंतरिक और बाह्य संघर्ष आदि दक्षिण एशिया में लोकतंत्र की नई लहर का सामना करने की चुनौती है।

सुसन हैंगेन की पुस्तक 'राइज ऑफ एथनिक पॉलिटिक्स इन नेपाल डेमोक्रेसी इन द मार्जिन्स' जातीय राजनीतिक दल मंगोल राष्ट्रीय संगठन (MNO) पर केन्द्रित है जिसमें अनेक जातीय समूह शामिल है जो पूर्वी ग्रामीण नेपाल में अपना समर्थन जुटा रहे हैं। यह पुस्तक अनुसंधान के द्वारा 1990 के दशक में ग्रामीण नेपाल में लोकतान्त्रिककरण की प्रक्रिया तथा दलीय विमर्श और संघर्ष के द्वारा प्राप्त किए जा रहे ग्रामीण सरकार के भीतर संचालन के लिए समर्थन को अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। उपर्युक्त अनुसंधान यह सूक्ष्म समझ हमारे समक्ष रखता है कि जातीय राजनीतिक दल सतह पर कैसे कार्य संपादित करते हैं? तथा यह तर्क रखता है कि जातीय आंदोलन सामाजिक आंदोलनों के साथ काफी हद तक समाप्त हो जाते हैं। और इसलिए दल और आंदोलन के मध्य की सीमा को पुनः परिभाषित किया जाना चाहिए। जैसे राजनीति और लोकतन्त्र के मध्य संबंध आमतौर पर विद्वानों और नीति निर्माताओं के लिए एक विरोधाभास प्रस्तुत करता है। नेपाली राजनीति में जातीय राजनीति तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही है। इस पुस्तक का तर्क है कि जातीय राजनीति में अस्थिर

करने की बजाए लोकतन्त्र को सशक्त करने की क्षमता है। सुसन हैंगन के द्वारा वर्षों के एथनोग्राफिक फील्डवर्क के द्वारा किया गया विश्लेषण यह दर्शाता है कि जातीय पक्ष विरोधी नहीं है बल्कि लोकतंत्रीकरण विविधता के साथ आगे बढ़ सकता है। यह तर्क नेपाल के स्वदेशी राष्ट्रियता आंदोलन में एक गहन चर्चा प्रदान करता है। यह मुख्य रूप से मधेशी आंदोलन का विस्तार से उल्लेख करती है।

महेंद्र लावोटी और सुसन हैंगेन द्वारा संपादित पुस्तक 'नेशनलिज्म एंड एथनिक कान्फ्लिक्ट इन नेपाल आइडेंटिटीस एंड मोबिलाइजेसन आफ्टर 1990' में नेपाली समाज में उन हाशिये के समूहों जैसे— मधेसियों, पहाड़ी दलितों, और मधेशी मुसलमानों की पहचान करके विस्तृत चर्चा की जो विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे हैं। लेखक ने जातीय राजनीति और जातीय विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की है। लेखक द्वारा पुस्तक में नेपाल में जातीय विविधता का विशद वर्णन शामिल है और इसलिए इन विविध जातीय समूहों के मध्य उत्पन्न होने वाले संघर्ष का विस्तार से वर्णन किया है। पुस्तक पहचान के संकट के बाहर उत्पन्न होने वाले विभिन्न आंदोलनों जैसे—जातीय संघर्ष और जातीय आंदोलनों पर तो दृष्टि डालती है परंतु मधेशी आंदोलन पर अधिक ध्यान केन्द्रित नहीं करती है (महेंद्र और सुसन, 2013)

निहार नायक का लेख 'द मधेशी मूवमेंट इन नेपाल: इंप्लीकेशन्स फॉर इंडिया' नेपाल की राजनीति में मधेसियों की बढ़ती भूमिका की पहचान करता है। नायक ने अपने लेख में तर्क दिया कि उच्च जाति के पहाड़ी (हिल) लोगों और नेपाली राज्य के द्वारा किए गए भेदभाव ने मधेशी पहचान को सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। वह उल्लिखित करते हैं कि मुख्यधारा के मधेशी दलों ने स्वतन्त्रता की मांग के लिए सशस्त्र समूहों की अपेक्षा नरम रुख अपनाया है। वह मधेसी आंदोलन के भीतर मौजूद मतभेदों और आंदोलन के विभाजन तथा इसमें भारत को घसीटने के मुद्दे का भी विस्तार से उल्लेख करते हैं। नायक यह चर्चा करते हैं कि यह स्थिति भारत और नेपाल के सम्बन्धों को प्रभावित करेगी और इससे नेपाल में भारत विरोधी भवनाएं उत्पन्न होंगी, परंतु नायक मधेशी आंदोलन की सीमाओं और उस पर राज्य की प्रतिक्रियाओं पर अधिक ध्यान केन्द्रित नहीं करते हैं।

1.4 शोध प्रश्न

- दक्षिण एशिया में उपनिवेशवाद ने राज्य-राष्ट्र (State & Nation) की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित किया है?
- नेपाल राज्य में लोकतन्त्र का उभार कैसे हुआ?
- नेपाल राज्य को दक्षिण एशिया में कैसे स्थापित किया जा सकता है?
- मधेशी आंदोलन के उद्देश्य क्या हैं और आंदोलन के बढ़ने के पीछे विभिन्न कारण क्या हैं?
- मधेशी आंदोलन के भीतर विभिन्न मधेशी समूहों और दलों के बीच संघर्ष क्या हैं?
- नीति निर्माण की प्रक्रियाओं में मधेशियों को एकीकृत करने के लिए समय पर क्या प्रयास किए गए हैं?
- मधेशियों को नेपाली राज्य की मुख्य धारा में समावेश की समस्या

1.5 शोध उद्देश्य

- दक्षिण एशिया में राज्य-राष्ट्र और राष्ट्र-राज्य के विमर्श को समझना।
- दक्षिण एशिया में नेपाल राज्य की स्थिति को समझना।
- नेपाल राज्य में राज्य-राष्ट्र और राष्ट्र-राज्य की स्थिति को समझना।
- नेपाल राज्य में राज्य-राष्ट्र की प्रक्रिया में मधेशी आन्दोलन की भूमिका को समझना।
- नेपाल राज्य में राज्य-राष्ट्र की प्रक्रिया में जातीय अंतर्द्वंद को समझना।
- नेपाल राज्य में राज्य-राष्ट्र की प्रक्रिया में आर्थिक अंतर्द्वंद को समझना।
- नेपाल राज्य में राज्य-राष्ट्र की प्रक्रिया में वैश्विक हस्तक्षेप की भूमिका को समझना।

1.6 शोध परिकल्पना

- दक्षिण एशिया और नेपाल राज्य दोनों में अंतर्द्वंद (Dilemma) की स्थिति समान है।
- राज्य-राष्ट्र और लोकतन्त्र के मध्य तालमेल नेपाल राज्य की सबसे बड़ी समस्या है।
- नेपाल राज्य की राजनीति पर्वतीय राज्य होने के कारण दक्षिण एशिया में भिन्न है।

1.7 शोध प्रविधि

शोध प्रविधि शोध करने की एक क्रमबद्ध योजना होती है। प्रस्तावित अध्ययन में गुणात्मक और द्वितीयक स्रोतों के साथ-साथ परिमाणात्मक शोध पद्धति का प्रयोग प्रकरण सम्बन्धी आधार (Contextual Basis) पर किया है। प्रस्तुत अध्ययन अपनी प्रकृति में सैद्धांतिक, व्यवहारिक, ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक है। प्रस्तुत अध्ययन में राज्य-राष्ट्र और राष्ट्र-राज्य के विमर्श को दक्षिण एशिया और विशेष रूप से नेपाल राज्य के सन्दर्भ में समझने का प्रयास किया गया है। उसके उपरांत नेपाल राज्य में राज्य-राष्ट्र के अंतर्द्वंद (State-Nation Dilemma) में नृजातीय, भाषाई, जातीय समूहों और मधेशी आन्दोलन की भूमिका का अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन के लिए क्षेत्र अध्ययन (Field Study) पद्धति का प्रयोग प्रासंगिक प्रकरणों के सन्दर्भ में किया गया है।

1.7.1 प्राथमिक स्रोत

प्रस्तुत शोध के लिए प्राथमिक स्रोत के रूप में एथनोग्राफी अध्ययन पद्धति को अपनाया गया है, क्योंकि मधेशीयों की कुछ विशेषताएं थीं जो सामान्य नहीं थीं। मैंने अपने शोध में उत्तरदाताओं के जवाबों को बिना किसी पूर्वाग्रह के प्रामाणिक रूप से दर्शाया है।

(a) अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत शोध के लिए अध्ययन का क्षेत्र झापा, मोरंग और नेपाल का सुनसारी, जिला था। झापा नेपाल का पूर्वी जिला है और उपजाऊ तराई क्षेत्र के मैदानों में स्थित है। यह उत्तर में ईलम जिला, पश्चिम में मोरंग जिला, बिहार राज्य, दक्षिण पूर्व में भारत और पश्चिम बंगाल की सीमा में आता है। जिले को 37 ग्राम विकास समितियों (वीडीसी) और 7 नगरपालिकाओं में विभाजित किया गया है। मोरंग, झापा के पश्चिम में स्थित है। इसमें 6 नगर पालिका और 47 ग्राम विकास समितियाँ हैं। सुनसारी में 42 ग्राम विकास समितियों (वीडीसी) और 5 नगर पालिकाओं हैं जो कि मोरंग के पश्चिम में स्थित है। झापा, मोरंग और सुनसारी के क्षेत्रों को निम्नलिखित कारणों से लिया गया था— 2015 के नए संविधान द्वारा नेपाल के प्रस्तावित 7 राज्यों में मधेशी राज्य 2 और थारु राज्यों की संख्या 5 है। राजनीतिक दृष्टि से मधेशी और थारु ऐसे दो राज्यों की मांग कर रहे हैं जिसमें दोनों में समतल मैदान हो। इनकी मांग के अनुसार इन दोनों राज्यों में कोई पहाड़ी क्षेत्र शामिल नहीं होना चाहिए। परंतु नेपाल के नए संविधान में 7 राज्यों के साथ वर्तमान संघीय मानचित्र में 3 क्षेत्र हैं जो मधेशियों और थारु की मांगों के अनुरूप नहीं है, और यही संघर्ष की जड़ है। जो नेपाल में राज्य-राष्ट्र की प्रक्रिया में एक अवरोध के रूप में कार्य कर रहा है।

ये प्रमुख कारण थे जिससे मधेशी अभी भी 2015 के संविधान द्वारा किए गए सीमांकन से संतुष्ट नहीं थे, जो मधेशियों के आक्रोश का कारण बन गया। इसलिए प्रस्तुत अध्ययन झापा, मोरंग और सुनसारी पर केन्द्रित है। क्योंकि झापा, मोरंग और इसलिए सुनसारी में मधेशियों और गैर मधेशियों की आबादी का उल्लेख करना महत्वपूर्ण हो जाता है।

(b) साक्षात्कार प्रक्रिया:

डेटा संग्रह के लिए प्राथमिक स्रोत 'सर्वेक्षण पद्धति' का प्रयोग किया गया है जिसमें साक्षात्कार के लिए एक प्रश्नावली का उपयोग किया गया है और डेटा को खुली चर्चा के माध्यम से एकत्र किया गया है। मैंने अपने इस शोध कार्य में 15 मधेशी

उत्तरदाताओं और इसी तरह 10 गैर मधेशी उत्तरदाताओं का साक्षात्कार लिया गया था। प्रस्तुत शोध नेपाल सरकार के प्रकाशनों और रिपोर्टों पर भी निर्भर करता था। साक्षात्कार की गोपनीयता और इसकी स्वैच्छिक प्रकृति को बनाए रखने के लिए सभी उत्तरदाताओं को नाम न प्रकाशित करने के लिए कहा गया था और साथ ही साथ उन्हें साक्षात्कार छोड़ने का विकल्प दिया गया था। उत्तरदाताओं को उनकी सुविधा के अनुसार साक्षात्कार के लिए बेहतर समय और स्थान पर बातचीत करने का विकल्प भी दिया गया और उन्हें शोध के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझाया गया।

1.7.2 द्वितीयक स्रोत

अखबार पुस्तकें पत्रिकाएँ लेख आदि का प्रयोग किया गया है जिनका अध्यायों में संदर्भ के रूप में उल्लेख किया गया है।

1.8 अध्यायों का संक्षिप्त परिचय:

प्रथम अध्याय : प्रस्तावना

द्वितीय अध्याय : राष्ट्र –राज्य और राज्य–राष्ट्र की अवधारणा एक सैद्धांतिक ढांचा

तृतीय अध्याय : दक्षिण एशिया में राज्य–राष्ट्र अंतर्द्वंद

चतुर्थ अध्याय : नेपाल राज्य के लोकतान्त्रिक विकास की रूपरेखा

पंचम अध्याय : नेपाल में राज्य–राष्ट्र के अंतर्द्वंद में मधेशी आन्दोलन की भूमिका

षष्ठम अध्याय : नेपाल राज्य–राष्ट्र अथवा राष्ट्र–राज्य

सप्तम अध्याय : उपसंहार

1.9 उपसंहार

नेपाल पिछले दशक में संरचनात्मक राजनीतिक बदलावों से गुजरा है। यहाँ लंबे समय से चले आ रहे हिंसक माओवादी शासन का अंत हुआ तथा मई 2008 में 239 वर्ष पुरानी राजतंत्रात्मक व्यवस्था का पराभाव हुआ। नेपाल को एक सफल राज्य–राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए संविधान सभा का गठन संविधान निर्माण के लिए हुआ, जिसका निर्माण निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से हुआ। वर्ष 2015 में

नेपाल के नए संविधान ने लोकतान्त्रिक संस्थाओं को सशक्त किया। इस नवीन निर्मित संविधान में राजतंत्र का कोई स्थान नहीं रहा तथा नेपाल ने एक संघीय (7 राज्य), गणतंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाया। परंतु इस नव-निर्मित संविधान में भी तराई-मधेसियों की भागीदारी और अधिकारों की समस्या मुख्य चुनौती के रूप में उभरकर सामने आई, जिसके परिणामस्वरूप नेपाल को अनेक संकटों और संघर्षों से गुजरना पड़ा, परंतु हम जानते हैं कि राज्य-राष्ट्र और संविधानवाद एक सतत् प्रक्रिया है जिसमें जनता की इच्छानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। इन नवीन परिवर्तनों से यह विश्वास किया जा सकता है कि आने वाला समय नेपाल में सही मायनों में एक राज्य-राष्ट्र एवं लोकतान्त्रिक संविधानवाद को स्थापित करेगा।

माओवादी प्रमुख प्रचंड और तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइराला ने 21 नवंबर 2006 को एक शांति प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए, जिससे आमजन को एक स्थिरता की आशा जगी। हिमालयन टाइम्स के लेख में कहा गया कि 'नेपाल शांति, लोकतंत्र और शासन के एक नवीन युग में प्रवेश कर चुका है'। दोनों के मध्य इस समझौते ने एक दशक से चले आ रहे माओवादी संघर्ष को समाप्त कर दिया। राजतंत्र के समाप्ति और माओवादियों के सत्ता में आने के पश्चात ही संवैधानिक सभा के चुनाव सम्पन्न हुए। ये चुनाव फर्स्ट-फास्ट-द-पोस्ट और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर सम्पन्न हुए। इस चुनाव में दलितों, जनजातियों, महिलाओं को यथास्थान प्रदान किया गया।

2006 के बाद की अवधि में, नेपाल ने राज्य-राष्ट्र निर्माण के एक नए चरण में प्रवेश किया है। दरअसल नेपाल में लोकतान्त्रिक राज्य-राष्ट्र निर्माण का नया चरण औपचारिक रूप से 2015 के संविधान की घोषणा के साथ प्रारम्भ होता है। परंतु राज्य-राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया सरल और आगे की चुनौतियों से अछूती नहीं है। अखंड सुदुर-पश्चिम और मधेस आंदोलन, लोकतंत्रीकरण, 2015 के संविधान के लिए तत्कालिक चुनौतियां थीं। इस प्रक्रिया में बहिष्करण और समावेशी अपनेपन के मध्य द्विभाजन का प्रबंधन अभी भी बहुत व्यापक चुनौती है। एक वैचारिक और सैद्धांतिक स्पष्टता तथा राजनीतिक दृष्टि के साथ इस द्वंद को प्रबंधित करने में विफलता

राज्य-राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया के अभियान को कमजोर कर सकती है। इसी तरह, व्यक्तिगत स्वायत्तता के आधार पर नागरिकता के अधिकारों से वंचित करने के साथ, लोकतांत्रिक मूल्यों को पुनः से एक लैंगिक (जेंडर) भेदभाव में समाहित कर दिया गया है। यह भेदभाव नागरिक पहचान के आधार पर समान नागरिकों और अपनेपन की भावना को दबा देती है। इसके अलावा नेपाल एकात्मक व्यवस्था के ढांचे से एक संघीय व्यवस्था के ढांचे में परिवर्तित हो रहा है, जो नेपाल के राजनीतिक इतिहास में एक नई संस्थागत व्यवस्था है। यदि नवीन संस्थागत संरचना नेताओं के सत्ता उन्माद द्वारा उत्पन्न अस्थायित्व को रोकने में असमर्थ है, तो संघवाद राजनीतिक उलटफेरों से भरा हो सकता है। कुल मिलाकर, नेपाल में राज्य-राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया की सफलता समान नागरिकों, निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी बाजार, सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा, एकीकरण, समावेशन और संवैधानिकता के आदर्शों को संस्थागत बनाने के लिए राज्य और संस्थानों की प्रभावी भूमिका पर निर्भर करती है जो कि कानून के शासन के रूप में सर्वोच्च है। नेपाल में एक उदार लोकतंत्र को संस्थापित करना राज्य-राष्ट्र निर्माण के लिए अहम है।

यह सम्पूर्ण शोध अध्ययन राज्य-राष्ट्र निर्माण की उस प्रक्रिया के स्वरूप की जांच करता है जो एक उदार लोकतंत्र के संस्थाकरण में परिणत होती है। चूंकि नेपाल में सत्तावादी या राजतंत्रीय शासन व्यवस्था समान नागरिकता की अवधारणा और कानून के शासन को सुनिश्चित करने में विफल रही हैं, इसलिए नेपाल में किसी भी सत्तावादी और राजतंत्रीय शासन व्यवस्था के लिए राज्य-राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को पूरा करना संभव नहीं हो पाया है। शोध अध्ययन का द्वितीय अध्याय राष्ट्र और राज्य की अवधारणा को व्यापक रूप से स्पष्ट करता है। एक राष्ट्र की अवधारणा उतनी सरल नहीं है जितनी कि दैनिक राजनीतिक विवेचन में निहित है। समान्यतया राष्ट्र को मौलिक अपनेपन और जुड़ाव के रूप में गलत समझा जाता रहा है। इस पृष्ठभूमि के विरुद्ध प्रस्तुत यह शोध अध्ययन में राजनीतिक-सामाजिक संगठन राजतंत्रीय व्यवस्था से एक संप्रभु राज्य-राष्ट्र और वैश्विक समाज तक राष्ट्रों के विकासवादी चरणों की भी व्यापक जांच करते हुए नेपाल में राज्य-राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।

नेपाल में अन्यायपूर्ण सत्ता संबंध, राजनीतिक संघर्षों और राजनीतिक अस्थिरता हमेशा से ही नेपाल में राज्य-राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के लिए चुनौतियों का मुख्य कारण रहे हैं। नेपाल के मामले से यह स्पष्ट होता है कि सत्ता का प्रयोग या तो अधिकारों से परे किया गया है या निहित राजनीतिक हितों अथवा व्यक्तिगत लाभ के लिए राजतंत्रीय व्यवस्था द्वारा किया गया है। अतः नेपाली राज्य में सत्ता सम्बन्धों की समस्या का समाधान व्यवस्था की सकारात्मकता से उत्साहपूर्वक किया जा सकता है। देखना होगा कि इस दिशा में 2015 का नवीन संविधान और संघीय संस्थान कितने मजबूत होते हैं।

राज्य-राष्ट्र निर्माण में सामाजिक समावेशन और राजनीतिक भागीदारी का अंतिम परिणाम समाज में समान नागरिकों के विचार को संस्थागत बनाना है। समान नागरिकों की अवधारणा का तात्पर्य यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को धन और संसाधनों के मामले में समान होना चाहिए, जो कि वास्तविकता में यूटोपियन और असंभव है। फिर भी, जो सैद्धांतिक और व्यावहारिक रूप से संभव है, उसे गंभीरता से हासिल किया जाना चाहिए। नेपाल के संदर्भ में इसके लिए कम से कम तीन विशिष्ट कार्यो या कार्यक्रमों की आवश्यकता है। सबसे पहले जाति व्यवस्था का न केवल सैद्धांतिक रूप से बल्कि लोगों की मानसिकता से भी उन्मूलन करना आवश्यक है। सैद्धांतिक रूप से 2015 के संविधान, अंतरिम संविधान और नेपाल के अन्य कानूनों ने जाति व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। हालांकि यह अभी भी लोगों की मानसिकता में है और सामाजिक दायरे में व्यापक रूप से प्रचलित है। दूसरा, एक सक्षम और सुखद वातावरण लोगों की पसंद का विस्तार करना पूर्ण और सापेक्ष गरीबी दोनों को कम कर सकता है और प्रतिस्पर्धात्मक रूप से गुणात्मक मानव संसाधन का निर्माण कर सकता है। सक्षम वातावरण में एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा, मानव संसाधनों का संशोधन और कानून का शासन शामिल है। तीसरा, सत्ता के अन्यायपूर्ण संबंधों को समाप्त करने के लिए सत्ता और अधिकारों के ढांचे के भीतर सत्ता को वैध बनाया जाना चाहिए। कई अन्य गंभीर समस्याओं के बीच, लैंगिक भेदभाव पर आधारित नागरिकता नीति यह स्पष्ट करती है, कि अन्यायपूर्ण शक्ति संबंध लोगों में सामाजिक संरचना में अपनेपन और जुड़ाव की पूर्ण भावना के साथ एकीकृत करने के अवसरों

को कैसे व्यापक रूप से नष्ट कर रही है। यह वह जगह है जहां स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक राजनीतिक नेतृत्व की गंभीर भूमिका सबसे स्पष्ट है।

शक्ति संबंधों का विश्लेषण महत्वपूर्ण है क्योंकि सत्ता में किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को या तो कानून व्यवस्था के शासन की ओर या कानून व्यवस्था के शासन की दिशा में चलाने की पूरी क्षमता है। कानून व्यवस्था द्वारा बनाए गए नियमों के तहत कानून केवल ऐसे उपकरण हैं जो राजनीतिक हितों की सेवा करते हैं, जिसे नेपाल ने अपने पूरे इतिहास में अनुभव किया है। कानून का शासन एक ऐसी प्रणाली है जहां सकारात्मक कानूनी ढांचे से परे कोई शक्ति मौजूद नहीं है, जो केवल अधिकार और अधिकारों के रूप में शक्ति को वैध बनाती है। 2015 के संविधान और संघीय ढांचे की सफलता इस बात से गहराई से प्रभावित होगी कि हम सैद्धांतिक रूप से किस प्रणाली को चुनते हैं और हम इसे व्यवहार में कैसे लागू करते हैं। यह चुनाव भी तय करेगा नेपाल में अपनेपन की भावना को मजबूत करने में सहभागी लोकतंत्र की प्रकृति और दायरा जैसा कि जॉन रॉल्स ने सुझाव दिया था, सामाजिक और आर्थिक वर्गों की समस्याओं को हल करने के लिए दो तरीके अपनाए जा सकते हैं। पहली स्वतंत्रता की प्राथमिकता है, यानी, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के संदर्भ में सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, जिसे जाति, जातीयता और असमान नागरिकता की स्थिति सहित किसी भी पूर्व शर्त के अधीन नहीं किया जा सकता है। दूसरा दृष्टिकोण असमानता के प्रबंधन पर आधारित है, अर्थात् यदि कोई व्यक्ति क्षमता, संसाधनों और कौशल के मामले में असमान होने के कारण दूसरों के लिए समान रूप से स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का आनंद नहीं ले सकता है, तो रॉल्सियन शब्दों में सिर्फ संस्थान आवश्यक हैं। असमानता का प्रबंधन करके अक्षम, गरीब और अकुशल व्यक्तियों को क्षमता निर्माण, संसाधनों तक पहुंच हासिल करने और कौशल बढ़ाने के द्वारा नियोजित गतिविधियों के साथ ऊपर उठाया जा सकता है। रॉल्स के लिए, इन जिम्मेदारियों को निभाने वाली संस्थाएँ ही न्यायसंगत हैं। दूसरे शब्दों में, केवल संस्थाएँ ही एक सुव्यवस्थित समाज की स्थापना कर सकती हैं, जो सच्ची भावना से राज्य-राष्ट्र निर्माण की परियोजना को पूरा करती है।

रॉल्स आगे इस बात पर जोर देते हैं कि, यदि लोग और संस्थाएं एक सुव्यवस्थित समाज के इन बुनियादी विचारों पर कार्य करने में विफल हो जाते हैं तो परिणाम गंभीर होंगे। जब व्यक्ति और समूह केवल व्यक्तिगत हितों का पीछा करते हैं, तो उनके लिए न्याय की भावना होना असंभव है। इस मुद्दे को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका यह सुनिश्चित करना है कि, चाहे स्वयं या समूह के उद्देश्यों से नागरिकों को ऐसे तरीकों से कार्य करने के लिए राजी किया जाए जो भलाई के योग को अधिकतम करते हैं। शायद, क्षमता निर्माण, संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करने और कौशल बढ़ाने के लिए मजबूत कार्यक्रमों और गतिविधियों को डिजाइन करके नेपाली राज्य को प्रभावी ढंग से पुनर्गठित किया जा सकता है और अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण बन सकता है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में राज्य, राष्ट्र, राष्ट्रवाद, राष्ट्र-राज्य, राज्य-राष्ट्र की अवधारणाओं को व्यवस्थित रूप से व्याख्यायित करने का प्रयास किया गया है। जहां राज्य एक राजनीतिक धारणा है वहीं राष्ट्र एक सांस्कृतिक धारणा है। जबकि राष्ट्रवाद एक विचारधारा है, वहीं राष्ट्र-राज्य एक प्रकार का राज्य है जो किसी राज्य की राजनीतिक इकाई को उसकी सांस्कृतिक इकाई के साथ मिलाता है। जबकि राज्य-राष्ट्र एक आधुनिक विमर्श है जो यह मानता है कि एक राज्य के अंतर्गत प्रथक प्रथक राष्ट्र अस्तित्व में हो सकते हैं।

वैश्वीकरण की अवधारणा आने के बाद विश्व के सभी राष्ट्र-राज्य आपस में घनिष्ठ रूप से इतने मिल-जुल गए हैं कि राष्ट्र-राज्य की अवधारणा का पतन हुआ है। दूसरी तरफ राज्य-राष्ट्र एक आधुनिक विमर्श के रूप में उभरा है जिसे वर्तमान तृतीय विश्व के देशों के संदर्भ में समझा जा सकता है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपनाया जाना एक सकारात्मक पहलू है। परंतु दूसरी तरफ नृजातीय संघर्ष, सांप्रदायिक संघर्ष निर्वाचित सरकारों का सैनिक शासन द्वारा तख्तापलट, राज्य और अंतर राज्य संघर्ष सुरक्षा का अंतर्द्वंद अलगाववाद क्षेत्रवाद आदि उसके नकारात्मक पहलू को उजागर करते हैं। और यह सभी अब दक्षिण एशिया के देशों में राज्य-राष्ट्र अंतर्द्वंद को जन्म दे रहे हैं। जिससे इस क्षेत्र

में राज्य-राष्ट्र की प्रक्रिया के समक्ष गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं अगर हम दक्षिण एशिया के देशों को राज्य-राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है तो इन नकारात्मक तत्वों को यथाशीघ्र समाप्त करने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशियाई देशों में राजनीतिक स्थायित्व, सशक्त लोकतान्त्रिक व्यवस्था को स्थापित करना धार्मिक संघर्षों और पृथकतावादी आंदोलनों को समाप्त करने का गंभीर प्रयास करना होगा।

नेपाल राज्य के लोकतान्त्रिक विकास की रूपरेखा अध्याय के अंतर्गत नेपाल में राजशाही से लेकर लोकतान्त्रिक व्यवस्था की स्थापना तक का विस्तृत वर्णन किया गया है। नेपाल में 1950 के जन-आंदोलन के द्वारा राणाशाही की समाप्ति तथा राजा त्रिभुवन की सत्ता के अधीन संवैधानिक राजतंत्र लागू करने की घोषणा की गई। राणा मोहन शमशेर, राजा त्रिभुवन और नेपाली कांग्रेस के मध्य अन्तरिम सरकार के गठन को लेकर 1951 में हुए समझौते से नेपाल में लोकतान्त्रिक प्रक्रिया का आरम्भ हुआ।

1950-51 का जन-आंदोलन आंतरिक और बाह्य शक्तियों के प्रभावी सहयोग का परिणाम था। राणा, राजा और राजनीतिक दलों जैसे हित समूहों को संतुष्ट कर एक नई व्यवस्था का विकास किया गया। इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि 1950-51 के जन-आंदोलन से नेपाल का लोकतान्त्रिक व्यवस्था से सिर्फ स्पर्श ही हो पाया था और तीनों हित समूहों राणा, राजा और राजनीतिक दल के मध्य नेपाल एक प्रकार से सत्ता संघर्ष का मंच बन गया था। राजनेताओं की अनुभवहीनता एवं अक्षमता के कारण राजा त्रिभुवन नेपाल में क्रांति के जनक के रूप में लोकप्रिय नेता बन गए। राजा ने अपनी इस लोकप्रियता का लाभ उठाते हुए अन्तरिम संविधान में कई संशोधन कर निरपेक्ष राजा के रूप में राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त कर लिया और संविधान सभा के चुनावों को आसानी से नाकाम कर दिया।

2006 में राजशाही की समाप्ति के पश्चात लोकतान्त्रिक व्यवस्था की स्थापना संविधान सभा के चुनाव एवं संविधान निर्माण के प्रयासों का विस्तृत वर्णन इस अध्याय में प्रस्तुत किया गया है। नेपाल में 20 सितंबर 2015 में नेपाल में नया संविधान स्वीकार कर लिया गया।

मधेशी आंदोलन ने नेपाल के सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तनों में बहुत अहम योगदान दिया है। मधेशी आंदोलन के पश्चात मधेशियों के प्रति नकारात्मक रुख और धारणा काफी हद तक कम हो गई है। इससे पूर्व मधेशी शब्द का प्रयोग पहाड़ी और काठमाण्डू के लोगों के मध्य अपमानजनक शब्द के रूप में किया जाता था। सभी उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया कि मधेशियों के प्रति मुख्यधारा के लोगों का पुराना रुख अब परिवर्तित हो गया है। क्षेत्र में एथनोग्राफिक अध्ययन से पता चला कि मधेशी आंदोलन ने मधेशियों को कैसे सशक्त बनाया।

सबसे पहले मधेशी आंदोलन ने राष्ट्रीय स्तर पर मधेशी पहचान को स्वीकार करने में अहम भूमिका का निर्वाह किया। इस आंदोलन ने नेपाली पहचान की पारंपरिक अवधारणा को खारिज कर दिया, क्योंकि यह सिर्फ पहाड़ी संस्कृति को मान्यता प्रदान करती थी। इससे पहले मधेशियों के साथ काठमाण्डू और पहाड़ी क्षेत्र में गैर-नेपाली के रूप में व्यवहार किया जाता था। मधेशी आंदोलन के फलस्वरूप मधेशी पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई तथा संविधान में मधेशी शब्द को भी शामिल किया गया। आंदोलन के पश्चात नेपाली राज्य के नीति, विकास, समावेशन और बजट के संदर्भ में सकारात्मक पहल ने मधेशियों को प्राथमिकता दी। इस आंदोलन ने समवेशी लोकतन्त्र को स्थापित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। इसके अलावा संविधान सभा में मधेशियों की संख्या में इजाफा हुआ। उदाहरण के लिए, राजनीतिक क्षेत्र में मधेशियों की भागीदारी 36.42 प्रतिशत (जबकि मधेशी आबादी 33 प्रतिशत) पहाड़ी मूल के जनजातीय लोगों की 34.33 प्रतिशत और दलितों की 11.94 प्रतिशत बढ़ी। इससे पूर्व संसद में मधेशियों का केवल 20 प्रतिशत ही प्रतिनिधित्व था। इस आंदोलन के पश्चात जनसंख्या के आधार पर चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों की वृद्धि के चलते मधेशी अब अपनी कुल जनसंख्या के 51 प्रतिशत भाग का प्रतिनिधित्व करता है जबकि 2008 से पूर्व सिर्फ 90 निर्वाचन क्षेत्र थे परंतु चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों में वृद्धि के पश्चात इनकी संख्या 119 हो गई। मधेशी आंदोलन अपनी प्रकृति में ऐतिहासिक था जिसने अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर जोर दिया। इसके अलावा मधेशी आंदोलन के पश्चात नेपाली गणतन्त्र के प्रथम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को मधेशी समुदाय से चुना गया था। कुल मिलाकर इस आंदोलन से

राज्य की नीति में ढांचागत बदलाव आया। मधेशी आंदोलन के पश्चात मधेशी जन अधिकार फोरम और तराई-मधेश पार्टी जैसे क्षेत्रीय राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे और उन्होंने केंद्रीय गठबंधन सरकार में भाग लिया।

संक्षेप में राज्य-राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ-पहचान का प्रबंधन, समान नागरिक के लिए सुखद वातावरण बनाना, सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करना केवल संवैधानिक शासन की प्रणाली के तहत ही संभव हो सकता है। अर्थात् एक उदार लोकतन्त्र जहां राजनीतिक विचारधाराओं सहित सभी प्रकार के शक्ति संबंध संविधान के दायरे में लाये जाते हैं। इसलिए उदार लोकतन्त्र की अवधारणा को राज्य-राष्ट्र निर्माण के मूल में दृढ़ता के साथ खड़ा होना चाहिए। वास्तव में उदार लोकतन्त्र राज्य-राष्ट्र निर्माण का एक सशक्त आधार है।

दक्षिण एशिया के 7 देशों में से तीन में यथा (भारत, भूटान और नेपाल) में धर्मयुक्त पंथ निरपेक्ष उदारवादी प्रजातांत्रिक व्यवस्था है वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान, मालदीव इस्लामिक राज्य है दूसरी ओर बांग्लादेश इस्लामिक ढांचे से बाहर आया है परंतु वहाँ इस पंथ निरपेक्ष ढांचे के विरुद्ध आंदोलन चल रहे हैं। नेपाल की स्थिति दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तुलना में अलग है जिसकी सीमा भारत और चीन से लगती है। जहां चीन में सर्वाधिकारवादी एकदलीय साम्यवादी शासन व्यवस्था है जो न केवल दक्षिण एशिया में प्रजातांत्रिक राज्यों के समक्ष चुनौतियां पैदा कर रहा है बल्कि समूचे वैश्विक राजीतिक संकट को उत्पन्न कर रहा है। एकदलीय बंद व्यवस्था से उत्पन्न आर्थिक समृद्धि से युक्त चीन अपने साम्राज्यवाद का विस्तार कर अपने समस्त पड़ोसी राज्यों के साथ विस्तारवादी मंसूबे के साथ कार्य कर रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि ऐसे हालात में यदि नेपाल में धर्मयुक्त पंथ निरपेक्ष उदारवादी प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं सुरक्षित रहती है तो उससे दक्षिण एशिया में असंतुलन उत्पन्न होने की प्रबल संभावना है। दक्षिण एशिया पर दो रंग यथा लाल रंग से लैस साम्यवादी विचारधारा और पाकिस्तान के पड़ोस में उत्पन्न हरे रंग में रंगे गैर प्रजातांत्रिक, गैर-पंथ निरपेक्ष इस्लामिक शासन से युक्त अफगानिस्तान और ईरान

स्पष्ट रूप से दक्षिण एशिया में प्रजातन्त्र के विरुद्ध चुनौती उत्पन्न कर रहे हैं। साम्यवादी और इस्लामिक विचारधारा राज्य-राष्ट्र विरोधी हैं जहां चीन साम्यवाद के माध्यम से एक वैश्विक राज्यविहीन समाज के सपने संजोय हुए हैं वही पर इस्लामिक व्यवस्था एक वैश्विक इस्लामिक राज्य स्थापित करने के लिए मदान्ध है। ये दोनों विचारधाराएं राज्यों और प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न कर रही हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो नेपाल विश्व की उच्चतम पर्वत श्रृंखला को अपने गर्भ में समेटे अपनी सामरिक अवस्थिति के चलते विश्व में सामरिक एवं पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण राज्य है। इसकी एक लंबी सीमा चीन के साथ लगी है तो दूसरी तिब्बत से लगी है, यह स्थिति स्पष्ट करती है कि नेपाल यदि हरे और लाल रंग की वैचारिक आँधी की चपेट में आता है तो इसका कुप्रभाव दक्षिण एशिया के साथ साथ वैश्विक राजनीति पर भी पड़ेगा। लंबे समय तक ब्रिटिश शासन ने भूटान, नेपाल और अफगानिस्तान को चीन और रूस के खिलाफ एक बफर राज्य के रूप में निर्मित किया था, जिससे न केवल दक्षिण एशिया में बल्कि पूरे विश्व में शक्ति का संतुलन बना रहा। यदि नेपाल चीन के साथ अपने सामरिक संबंधों में आगे बढ़ता है और अपने राज्य-राष्ट्र की विविधता को संरक्षित करने में असफल हो जाता है तो सीधे तौर पर चीन के माध्यम से भारत के लिए खतरा उत्पन्न करता है तो भारत के समक्ष रूस और यूक्रेन की कहानी के दोहराने का पूर्वाभास होता है। जो नेपाल के राज्य-राष्ट्र के अस्तित्व के लिए असपष्ट रूप से एक नाकारात्मक बात होगी।

इस शोध अध्ययन में शोधार्थी के द्वारा तीन परिकल्पनाएं रखी गई थी जो निम्नलिखित हैं—

प्रथम परिकल्पना— दक्षिण एशिया और नेपाल राज्य दोनों में अंतर्द्वंद (Dilemma) की स्थिति समान है। यह मेरे शोध अध्ययन से सिद्ध होती है क्योंकि दक्षिण एशिया और नेपाल में राजनीतिक अस्थायित्व (भारत को छोड़कर), मजहबी अंतर्द्वंद, नृजातीय अंतर्द्वंद, भाषाई अंतर्द्वंद की स्थिति समान हैं तथा सभी दक्षिण एशियाई देश इस स्थिति का सामना कर रहे हैं जो नेपाल को एक राज्य-राष्ट्र के रूप में सफलतापूर्वक स्थापित होने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधाएं हैं।

द्वितीय परिकल्पना: राज्य-राष्ट्र और लोकतंत्र के मध्य तालमेल नेपाल राज्य की सबसे बड़ी समस्या है यह भी मेरे शोध अध्ययन की कसौटी पर खरी उतरती है क्योंकि अधिकांश समय नेपाल में लोकतान्त्रिक व्यवस्था के आस्थायित्व और अनिश्चितता ने नेपाल को एक राज्य-राष्ट्र के रूप में कमजोर करने का कार्य किया है तथा नेपाल में लोकतन्त्र के उन्नत होने में राजतंत्र प्रमुख बाधा है, यह भी मेरे अध्ययन से सिद्ध होता है।

तृतीय परिकल्पना: नेपाल राज्य की राजनीति पर्वतीय राज्य होने के कारण दक्षिण एशिया में भिन्न है, यह भी मेरे शोध अध्ययन से सिद्ध होता है, क्योंकि दक्षिण एशिया के अन्य देशों के सापेक्ष नेपाल पूर्ण रूप से एक भू-बध्य राज्य-राष्ट्र है, जो दो महाशक्तियों भारत और चीन के राजनीतिक और आर्थिक हितों के संघर्ष से निरंतर प्रभावित रहता है।

शोध अध्ययन में निर्धारित तीनों परिकल्पनाएं मेरे शोध अध्ययन से सिद्ध होती हैं। शोध अध्ययन में शोधार्थी के द्वारा कुछ अनुशांसाएं एवं सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं जो निम्नलिखित हैं—

1. नेपाल के लिए भारत और चीन के बीच एक संतुलित संबंध बनाना महत्वपूर्ण है राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक समृद्धि।
2. समान नागरिक के लिए सुखद वातावरण बनाना।
3. स्थिर राजनीतिक व्यवस्था।
4. नेपाली राज्य-राष्ट्र को मधेशियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक प्रावधान करने चाहिए
5. नेपाल में राज्य-राष्ट्र ढांचे को अपनाया जाना आवश्यक है यदि नेपाल में चीन के साम्राज्यवादी और विसतारवादी मंसूबों और हस्तक्षेप को रोकना है।
6. नेपाली समाज बहुसांस्कृतिक, बहुभाषाई समाज रहा है, नेपाल को प्रजानतांत्रिक रखना विश्व की शांति और व्यवस्था के लिए आवश्यक है।